least 10 per cent of their total advances or 25 per cent of their priority sector advances. Madam, I would like to know whether, in view of the steep decrease in the value of the rupee and the corresponding increase in prices of inputs in the country, the Government would consider increasing this 10 per cent ratio and revise the guidelines of the Reserve Bank to make it 20 per cent for the benefit of the weaker sections and small and marginal farmers.

श्री दलबीर सिंह : उपसभापति जी, यह तो सजशंस हैं । इन पर हम विचार करेंगे । मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने 22 अप्रैल, 1992 से ऋणों के छह स्लैब थे, उन्हें हमने चार कर दिया है । 7,500 रुपये क 11.5 प्रतिशत ब्याज, 7,500 से 25,000 तक 13.5 प्रतिशत और इसी तरह 25,000 से दो लाख रुपये तक 16.5 प्रतिशत और 2 लाख से ऊपर 19 प्रतिशत किया है । इसमें जो लघु किसानों और लघु धंधों के लिए पच्चीस हजार से दो लाख तक की जो सीमा है, उसमें न्यूनतम ब्याज दर 15 प्रतिशत है ।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस पर हम विचार करेंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 544—Shri Ram Gopal Yadav.

श्री छोटूभाई पटेल : मैडम, यह सवाल पूछा था.. (**व्यवधान**)

उपसभापति : नहीं । ठीक है, वह जवाब हो जाएगा, फिर करवा देंगे ।

The question is not correct. When the answer comes correctly, then I will allow. Yes, Shri Ram Gopal Yadav.

Telephones at village panchayats

*544. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

SHRI RAM GOPAL YADAV:†

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the number of telephones installed in various panchayats, State-wise, as per the latest figures available;

(b) whether it is a fact that telephones meant to be installed at village panchayats are actually installed at some other places;

(c) if so, whether his Ministry has received any complaints from the villagers in this regard; and

(d) what steps are being taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): (a) 71,274.

Details are given as per the statement laid on the Table of the House. (*See below*)

(b) No, Sir. As per existing policy, telephones in Panchayat villages are provided at any of (i) Post Offices (ii) Panchayat Offices (iii) Grocer's shops or other suitable places with good public access.

(c) and (d) Yes, Sir. Some complaints have been received. which are sorted out in accordance with the existing policy.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Gopal Yadav.

Statement

Status of Panchayat Telephones as on 31-7-1992

Sl. No.	State	Panchayat Villages with Telephones facility as on 31-7-1992
1	Andhra Pradesh	10558
2	Assam	765
3	Bihar	4400
4	(i) Gujarat	4118
	(ii) Dadra Nagar, Daman & Diu	16
5	Haryana	2676
6	Himachal Pradesh	932
7	Jammu & Kashmir	483
8	Karnataka	4863
9	Kerala	982
10	Madhya Pradesh	8444
11	(i) Maharashtra	6816
	(ii) Goa	162
12	*North East :*	
	(i) Arunachal Pradesh	85
	(ii) Manipur	89
	(iii) Meghalaya	133
	(iv) Mizoram	36
	(v) Nagaland	19
	(vi) Tripura	176
13	Orissa	2679
14	Punjab	1971
15	Rajasthan	4016
16	(i) Tamil Nadu	8054
	(ii) Pondicherry	11
17	Uttar Pradesh	6980
18	(i) West Bengal	1566
	(ii) A & N Islands	17
	iii) Sikkim	44
19	Delhi U. T.	183
	TOTAL	71274

श्री राम गोपाल यादव : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसका (ख) भाग जो है, उसी से संबंधित शिकायतें हैं ।

प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायतों में टेलीफोन इंस्टाल करने के लिए पंचायतों को प्राथमिकता किस आधार पर तय होनी चाहिए, इसकी कोई गाईडलाईंस क्या मंत्री जी के यहां हैं?

दूसरी यह कि जिन पंचायतों का चयन होता है, उनमें गाईडलाईंस से हट कर अगर मनमाने तरीके से अधिकारी टेलीफोन इंस्टाल करते हैं और उनकी शिकायत की जाती है, तो क्या इस शिकायत के निवारण के लिए कोई समय सीमा है ?

श्री राजेश पायलट : मैडम, यह सरकार की नीति है कि 31 मार्च 1955 तक सारे देश की पंचायतों को हम टेलीफोन से जोड़ें तो हमने इसमें कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है कि पहले किन पंचायतों को जोड़ें । यह अधिकारियों के ऊपर है । हमारे टार्गेट के अनुसार 100 पंचायत हर रोज के हिसाब से सारे देश में जोड़ी जा रही है । मुझे खुशी है इस सदन को बताने में कि इस टार्गेट के साथ हम चल रहे हैं और पिछले साल टार्गेट 12 हजार का था लेकिन हम 21 हजार गांवों को जोड़ पाए हैं । इस साल हम 36 हजार 5 सौ पंचायतों का टार्गेट ले कर चले हैं और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक मार्च 1993 तक हम 36 हजार से ज्यादा ही पंचायतें जोड़ पायेंगे । दूसरी बात जहां तक शिकायतों की है मैडम, एक नई प्रणाली हमने गांवों में शुरु की है । शुरु-शुरु में इसमें कुछ टीथिंग प्राब्लम्ज होंगी गांवों में टेलीफोन लग रहे हैं, अभी तो लोगों में शौक बहुत बढ़ रहा है, किसी गांव में जब टेलीफोन लगाने जाते हैं तो वहां दो पार्टियां हो जाती हैं । एक तो वह जो चुना हुआ सरपंच होता है और एक वह जो सरपंच हारा हुआ होता है और दोनों में झगड़े होते हैं कि मेरे घर लगाओ, मेरे घर लगाओ । हमने फैसला किया है कि अगर उस गांव में डाकखाना है तो हम डाकखाने या ऐसी जगह जैसे कि दुकान है या कोई और ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे एवेलेबल हो और लोगों की सेवा कर सके, क्योंकि उसको 20 परसेंट इसमें कमीशन भी हम दे रहे हैं । लेकिन इसमें शुरुआत में परेशानियां जरुर आ रही हैं । शिकायतों का जहां तक सवाल है हमने शुरु में उनको प्रिंटेड पोस्ट कार्ड दे दिए हैं कि अगर आप बता भी नहीं पाओ कि अगर कोई टेलीफोन खराब हो जाए तो इस चिट्ठी को लिख दो और यह चिट्ठी एक्सचेंज में पहुंच जायेगी और उसे ठीक करने के लिए कर्मचारी वहां पर आ जायेंगे । ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए हैं ।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister consider....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing it.

Mr. Yadava, second supplementary.

श्रीमती रेणुका चौधरी : हमारी भी कोई शिकायत है, जनाब साहब ।

Please see that there is a system like this.

हम भी पोस्टकार्ड लिख देंगे ।... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please.

श्री राम गोपाल यादव : मैडम, यह जो मंत्री जी ने कहा कि गांव में एक सरपंच चुना हुआ होता है और एक हारा हुआ होता है उससे हमारा मतलब नहीं है, कहीं-कहीं और बहुत सी जगहों पर माननीय मंत्री जी के द्वारा ही स्वयं समस्यायें क्रिएट की गई और फार एग्जैंपल उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में अकेले... **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप अब यह डिटेल अगर एक-एक जिले की है तो आप मंत्री जी को लिख कर भेज दीजिए । मुझे दूसरा नाम भी बोलना है ।

श्री राम गोपाल यादव : नहीं-नहीं, शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं; माननीय मंत्री जी ने 37 पंचायतों की

स्वयं प्रायरिटी तय कर दी कि वहां लगेगा और जो गाइडलाइन हैं उससे हटकर कर दिया । इसी तरह से एक चिट्ठी 30 जनवरी को डा० सुब्रहमण्यम स्वामी ने लिखी 17 फरवरी को मंत्री जी का जवाब आया है । 6 महीने उसको भी हो गए, आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ । इसलिए मैंने सवाल किया था कि आप जैसे कंपीटेंट मिनिस्टर के होते हुए भी... **(व्यवधान)**

उपसभापति : मि० फर्नांडिस ।

श्री राम गोपाल यादव : अगर शिकायत का इतनी देर में निस्तारण हो तो समस्या का समाधान कैसे होगा ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Fernandes, you ask your supplementary.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, the hon. Minister has given a general reply stating that up to-date 71,274 telephone connections have been installed in the last 45 years in Panchayats in the country. The hon. Minister has announced an innovative scheme some time back stating that all the panchayats within a radius of 10 km. would be provided telephones on priority, even wireless telephones. May I know, in view of this new scheme, how many telephone connections have been allotted under this scheme out of these 71,274 telephone connections?

SHRI RAJESH PILOT: Madam, as far as part (a) is concerned, as I have said, the Government's policy is to provide telephones to each panchayat. He is right that in the last 45 years 71,000 is the total. But, he must also appreciate, Madam, that in the last one year, after the Government took over, we have had a target of 100 per day, and we have been able to add 21,000 villages. This is the first time when the Government has come out with a target per day, that we would be connecting 100 panchayats per day.

As far as the second part panchayats within 10 km. is concerned, I do not know where the hon. Member has read it. The policy is to give telephone connections to all panchayats at 10 km., 20 km., but if a panchayat is closer to the exchange, priority is given to that so that the connection can be given faster to that panchayat. Maybe, that is what is in the hon. Member's mind.

डा. संजय सिंह : माननीया महोदया, श्री राम गोपाल जी के सवाल के जवाब थे... **(व्यवधान)**

उपसभापति : इसीलिए पूछ रहे हैं... **(व्यवधान)** जो काम अधूरा छोड़ कर गए मैं... **(व्यवधान)**

डा० संजय सिंह : सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रामसभाओं के टार्गेट फिक्स किए हैं । मैं जानना चाहूंगा कि कुछ साल पूर्व अमेठी लोक सभा में हर ग्राम प्रधान के घर पर वायरलैस टेलीफोन लगाए गए थे जिसमें मुझे जानकारी है कि 50 परसेंट से ज्यादा टेलीफोन खराब हो चुके हैं । मैं जानना चाहूंगा कि उनको ठीक कराने की तुरंत कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : यह बात सही है, मैडम, पिछले वर्ष 1991 के चार-पांच महीने में वहां टेलीफोन कुछ ज्यादा ही खराब रहे थे । अब हमने उसमें सुधार की कोशिश की है । यह माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि अमेठी का हर टेलीफोन ठीक कर दिया जाएगा, जिससे माननीय सदस्य बात कर सकें। ... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question Hour is over.